

सीजी सिटी और आइटी सिटी को लेकर हुई **महत्वपूर्ण** बैठक

# 10 एकड़ पर 25 प्रतिशत विकसित या 50 प्रतिशत अविकसित भूमि मिलेगी

जासं • लखनऊ: वेलनेस सिटी और आइटी सिटी योजना को लेकर किसानों से चल रही खींचतान को खत्म करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। शनिवार को इन दोनों योजनाओं को लेकर डीएम सुर्यपाल गंगवार की अध्यक्षता में प्राधिकरण भवन के पारिजात सभागार में बैठक हुई, जिसमें किसानों की मांगों पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया। अधिकारियों का दावा है कि किसान प्रदर्शन स्थगित करने पर राजी हो गए हैं।

जिलाधिकारी ने किसानों को बताया कि प्रशासन व प्राधिकरण द्वारा उनके हितों का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 एकड़ व उससे अधिक क्षेत्रफल की भूमि की लैंड पूलिंग करने पर योजना में ही 25 प्रतिशत विकसित या फिर 50 प्रतिशत अविकसित जमीन देने का प्रविधान है। इसके अलावा 10 एकड़ से कम क्षेत्रफल में लैंड पूलिंग पर 25 प्रतिशत विकसित भूमि या भूखंड भूमि स्वामी को देने की व्यवस्था है।

## 153 व्यावसायिक चबूतरे आवंटित

जासं, लखनऊ: गोमती नगर फेज-2 व गोमती नगर विस्तार योजना में अधिग्रहीत की गई भूमि के प्रभावित किसानों को एलडीए ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। शनिवार को प्राधिकरण भवन के बारादरी लान में लाटरी से 153 पात्र किसानों को व्यावसायिक चबूतरे आवंटित किए गए। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर फेज-2 योजना के लिए उजरियांव, तखवा कटौता व हुसड़िया और गोमती नगर विस्तार योजना के लिए मलेशेमऊ व मकदूमपुर की जमीन अधिग्रहीत की गई थी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने किसानों के आवेदनों की दोबारा जांच कराकर जल्द चबूतरों की लाटरी कराने के निर्देश दिए थे।

किसानों की मांग पर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लैंड पूलिंग के तहत किसानों को दी जाने वाली भूमि का भू-उपयोग पहले से निर्धारित कर लिया जाए, जिससे कि किसानों को यह पता रहे कि उस भूमि पर किस तरह का निर्माण करवाया जा सकता है और वे इसका पूरा लाभ उठा सकें।

डीएम ने किसानों के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) से होने वाले लाभ के बारे में बताया। वहीं, रजिस्ट्री पर रोक के सवाल पर डीएम ने बताया कि

सक्षम स्तर से विशेष अनुमति लेकर निबंधन की कार्यवाही कराई जा सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के किसानों द्वारा निबंधन के लिए अनुमति मांगने पर त्वरित कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि किसान संगठन के नौ सूत्रीय मांग पत्र पर सक्षम स्तर से वार्ता करके कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विस्तृत चर्चा के बाद किसानों ने प्रदर्शन स्थगित करने पर सहमति जताई है। इस दौरान सचिव विवेक श्रीवास्तव व एडीएम राकेश सिंह व किसान संगठनों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।